

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 80 / दो-1-8 / 19
प्रति,

होशंगाबाद दिनांक 16.01.2021

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित भौतिक कामकाज शुरू किये जाने हेतु दिये गये दिशा निर्देश के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर दिनांक 15.01.2021

—00—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में परिवार न्यायालय सहित नियमित भौतिक कामकाज शुरू किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मैं **आलोक अवस्थी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद** दिनांक 18.01.2021 से आगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ जो तत्काल प्रभावशील होंगे-

- 1- यह कि सभी न्यायालयों में समस्त प्रकृति के प्रकरण सुनवाई में लिये जाएंगे।
- 2- यह कि समस्त न्यायालय नियम एवं आदेश में दिये गये समय अनुसार कार्य करेंगी एवं पीठासीन अधिकारी प्रतिदिन नियत किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या को इस प्रकार निश्चित करेंगे कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में भीड़ एकत्रित न हो।
- 3- यह कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए नियमित भौतिक सुनवाई तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों के माध्यम से सुनवाई की जाएगी।
- 4- यह कि प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दिवस सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरणों की कॉज लिस्ट तैयार कर सूचना पटल पर चरपा कर कॉज लिस्ट अनुसार प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
- 5- यह कि अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण की उपस्थिति के संबंध में आदेश पत्रिका में उल्लेख किया जावेगा किंतु कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण के आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर, जहाँ कानून के अनुसार अनिवार्य है, को छोड़कर नहीं लिये जावेंगे।

- 6— यह कि अदालत के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति विशेष कारण से निर्देशित किये जाने पर आवश्यक होगी अन्यथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाजरी माफी आवेदन के माध्यम से उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। विचाराधीन बंदी के मामले में प्रकरण में प्रथम रिमाण्ड के दौरान न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होगी तथा पश्चात् में अन्य रिमाण्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा सकेगी।
- 7— यह कि समस्त न्यायिक अधिकारी समन जारी करने की सामान्य प्रक्रिया के अलावा सी.आई.एस. एन.सी. 3.2 में दी गयी सुविधा का उपयोग करके संदेश के माध्यम से समन की सेवा का उपयोग करेंगे, जो समन की सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया गया है।
- 8— यह कि जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ के प्रवेश एवं निकासी के लिए सभी एहतियाती उपाय किये जावेंगे और न्यायालय में जनसमूह को सीमित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।
- 9— यह कि न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ के सदस्य जिनको क्वारंटीन या आईसोलेट किया गया है का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- 10— यह कि मद्यपान, गुटखा, पान तम्बाकू खाकर न्यायालय परिसर में थूकना पूर्णतः वर्जित रहेगा एवं कोई व्यक्ति ऐसा करता पाये जाने पर केन्द्र/राज्य शासन द्वारा जारी विधि व निर्देशानुसार अभियोजन व दण्ड के भागी होंगे।
- 11— यह कि न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण तथा स्टाफ के सदस्य न्यायालय में तर्क के दौरान तथा साक्ष्य लेखबद्ध किये जाते समय तथा अन्य समय न्यायालय परिसर में फेस मास्क का उपयोग इस तरह करेंगे कि नाक एवं मुंह ढका रहे।
- 12— यह कि सभी प्रवेश द्वार जहाँ से न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टाफ के सदस्य प्रवेश करते हैं वहाँ पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनकी थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कार्य हेतु नियुक्त किये गये स्टाफ द्वारा आवश्यक रूप से की जावेगी।
- 13— यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बुखार अथवा सर्दी—जुखाम जैसे लक्षण हों उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि स्टाफ का कोई सदस्य बुखार अथवा सर्दी—जुखाम जैसे लक्षणों से ग्रसित हो उसे तत्काल इस बात की सूचना अपने पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश को देनी होगी।
- 14— यदि किसी अधिवक्ता को बुखार अथवा सर्दी जुखाम के लक्षण हों तो वह तुरंत इसकी जानकारी संबंधित अधिवक्ता संघ एवं जिला न्यायाधीश को देगा।
- 15— यह कि जिला मुख्यालय होशंगाबाद सहित तहसील न्यायालयों के

क्षेत्र में कर्फ्यू/लॉकडाउन/कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के न्यायालय का कार्य बंद रहेगा, किन्तु अतिआवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए की जाएगी।

16— यह कि केवल ऐसे पक्षकारगण तथा उनके अधिवक्तागण को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके मामले सुनवाई हेतु नियत हों, इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्हीं अधिवक्तागण/पक्षकारगण को प्रवेश दिया जाए, जिनके मामले उस दिन सुनवाई हेतु नियत हों।

17— यह कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो इसको देखते हुए न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन एवं फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी।

18— यह कि अभिभाषक कक्ष, अधिवक्तागण के चेम्बर तथा बार लाईब्रेरी तभी खोली जाएंगी तब जबकि अभिभाषक संघ द्वारा कोविड-19 सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये हों। अध्यक्ष अभिभाषक संघ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 की सुरक्षा के सभी उपाय एवं सैनेटाईजेशन किया गया हो एवं अभिभाषक कक्ष में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।

19— यह कि न्यायालय परिसर जैसे न्यायालय कक्ष, न्यायाधीश कक्ष, ऑफिस, शौचालय एवं अन्य अनुभागों में समुचित सैनेटाईजेशन कराया जाए एवं मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय तथा न्यायालय के बरामदों में हैण्डवॉश एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था की जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में हाथ धोए अथवा हाथों को सैनेटाईज किये बगैर प्रवेश न कर सके।

20— यह कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता व पक्षकारों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगायी गयी हो तथा अन्य अधिवक्तागण एवं पक्षकार न्यायालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने प्रकरण की सुनवाई के लिए पुकार लगने तक इंतजार करेंगे।

21— यह कि न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टाफ के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। एक समय में न्यायालय कक्ष में अधिवक्ता, पक्षकार, साक्षीगण सहित 10 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी न्यायालय में पर्याप्त स्थान को देखते हुए अधिवक्ता, पक्षकार को न्यायालय में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। पीठासीन अधिकारी प्रकरणों की सुनवाई एक-एक करके करेंगे तथा अगले प्रकरण की सुनवाई से पहले 2 मिनट का अंतराल होगा, जिसमें न्यायालय में सैनेटाईजेशन किया जाएगा।

22— यह कि न्यायालय कक्ष में कुर्सी व बेंचों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा तथा न्यायालय व ऑफिस में स्टाफ की बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जावेगी।

23— यह कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय कक्ष, बरामदा, गैलरी व परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होगी।

24— यह कि न्यायालय कक्ष के बाहर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड सुचारु रूप से कार्यरत रखे जाएंगे तथा न्यायालय की कॉज लिस्ट संबंधित अधिवक्ता व पक्षकारगण की सुविधा के लिए डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी।

25— यह कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा जजमेंट एवं प्रकरणों की अगली सुनवाई की तिथि को वेबसाईट में जल्द से जल्द अपलोड किया जावे।

26— यह कि समस्त अधिवक्तागण प्रकरण से संबंधित अपनी फाईल संधारित करेंगे एवं प्रकरण की सुनवाई के पश्चात् तत्काल न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

27— यह कि शासन के निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों का मूवमेंट कम से कम किया जाना है इसलिए जो अधिवक्ता/सीनियर अधिवक्ता जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे न्यायालय परिसर में प्रवेश करते हैं तो समस्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए प्रवेश करें अन्यथा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

28— उपरोक्त दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा दिन प्रतिदिन वस्तु स्थिति को सुपरवाईज एवं मॉनिटर कर जिला न्यायाधीश को अवगत कराये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है –

जिला मुख्यालय होशंगाबाद:-

1. श्री सचिन शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश होशंगाबाद।
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, होशंगाबाद।
3. श्री अरुण कुमार शर्मा, उप प्रशासनिक अधिकारी, होशंगाबाद।

तहसील पिपरिया:-

1. श्रीमती कीर्ति कश्यप, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, पिपरिया
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पिपरिया।
3. नायब नाजिर, सिविल न्यायालय, पिपरिया।

तहसील इटारसी:-

1. श्री संजय कुमार पाण्डेय, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, इटारसी।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, इटारसी।
3. नायब नाजिर, सिविल न्यायालय इटारसी।

तहसील सोहागपुर:-

1. श्री अतुल खण्डेलवाल, अपर जिला न्यायाधीश, सोहागपुर।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सोहागपुर।
3. नायब नाजिर, सिविल न्यायालय, सोहागपुर।

तहसील सिवनी मालवा:-

1. श्री यशवंत कुमार मालवीय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिवनीमालवा

2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सिवनी मालवा।

3. नायब नाजिर, सिविल न्यायालय, सिवनी मालवा।

29- यह कि कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार का फंक्शन या पार्टी आयोजित नहीं की जावेगी।

30- यह कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

31- यह कि यदि कोई अधिवक्ता व पक्षकार उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसकी सूचना जिला न्यायाधीश द्वारा बार काउंसिल मध्यप्रदेश तथा संबंधित बार एसोसिएशन को देते हुए माननीय उच्च न्यायालय को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया जाएगा।

32- यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस परिपत्र के प्रभावशील होने की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए यूनिट मापदण्ड में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

33- यह कि यूनिट मापदण्ड के संबंध में पूर्व परिपत्र क्रमांक ए/2874 दिनांक 03.12.2020 की प्रभावशीलता इस परिपत्र के प्रभावित रहने तक के लिए बढ़ायी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तथा इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे।

संलग्न- मान. उच्च न्यायालय जबलपुर
का परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर
दिनांक 15.01.2021

आलोक अवस्थी
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)
होशंगाबाद दिनांक 16.01.2021

पृष्ठांकन क्रमांक 81/दो-1-8/19

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)

(6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

(7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद (म.प्र.)

(8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(9) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(10) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(11) सिस्टम ऑफिसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// SOP FOR SUBORDINATE COURTS //

No./ A/113/

Jabalpur dated 15/01/2021

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start regular physical functioning in the Subordinate Courts including Family Courts in respect of all category of cases w.e.f. 18.01.2021.

- (1) All types of cases will be taken up by the Courts subject to the directions issued by the District & Sessions Judge.
- (2) The District & Sessions Judge will have discretion to regulate the physical functioning in the Court including the nature and categories of cases, number of cases and timings of sitting of Judges depending upon the prevailing circumstances and effect of Covid-19 in the concerned district.
- (3) Depending upon the seriousness of Covid-19 effect, the District & Sessions Judge will have an option to switch to limited virtual hearing through video conferencing/mixed functioning through physical mode and video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.
- (4) The District & Sessions Judges will take immediate steps for installing the plastic curtain between the Judges/Reader, Staff AND Advocates/ litigants in each functional court room.

- (5) The District & Sessions Judge will ensure the publication of daily cause list showing the matter listed before different courts and the court concerned will take up the cases as per serial order in the daily cause list. The cause list will also disclose the cases to be taken up in pre-lunch session and post-lunch session.
- (6) The courts shall usually function as per timings of the courts specified in Rules and Orders, except at places where lockdown/shutdown is imposed or containment zone declared by the competent authority.
- (7) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files, and their signatures would not be taken on order sheet, statements (Except where law requires) to prevent the spread of Corona virus, till further orders.
- (8) Production of the accused before the court may be, unless specifically directed otherwise for any reason, accepted by video conferencing. However, the accused shall be required to be produced before the Magistrate for remand in the first instance. But, subsequent remand may be granted by video conferencing.
- (9) All the Judicial Officers are hereby impressed upon for the use of service of summons through the message by using the facility in the Software CIS NC 3.2 in addition to normal mode of service, which has been provided for in order to facilitate service of summons.

- (10) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.
- (11) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.
- (12) Persons consuming liquor, pan, gutkha or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.
- (13) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover, covering nose and mouth (including at the time of argument and tendering evidence). Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without wearing proper face mask.
- (14) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.

- (15) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.
- (16) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association with intimation to the District Judge.
- (17) Working of the Subordinate Courts / Family Courts in the State shall remain suspended in areas where curfew / lockdown / containment area has been declared by the competent authority. However, the court shall take up urgent matters and the intimation of the situation be communicated to the High Court.
- (18) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the restricted entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.
- (19) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding.
- (20) Bar Rooms, Advocates' Chamber, Bar Library shall remain open subject to adherence of all the safety norms. The Bar President shall

observe safety norms and ensure sanitization as well as limited entry through the Bar Room(s) to prevent crowding.

- (21) Proper sanitization of entire premises i.e. Court Rooms, chamber of Presiding Officer, offices, toilets and place of common use must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.
- (22) The District Judges should ensure installation of adequate numbers of wash basins in addition to arrangement of sanitizer so that the visitors/lawyers/staffs can properly sanitize their hands before entering the Court premises/complexes.
- (23) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.
- (24) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders. In no case at a time more than 10 persons (advocate / witness / party / accused) (subject to availability of space) will be allowed in a Court Room. Entry of number of persons in the Court Room will be as per the instructions issued by the concerning District Judge, keeping in view the space available in the Court Room. Cases shall be heard consecutively i.e.

one by one and a break of 2 minutes shall be given for proper sanitization before starting hearing of new case.

- (25) The Chairs/Benches in the Court Hall should be suitably arranged keeping in mind the social distancing norms. The sitting arrangement of staff in the Court and Offices shall also be made compliant to social distancing norms.
- (26) At no circumstances the Court Hall or Court Varanda / common passages / corridors or Court premises shall be crowded. Congregation in any form is to be prevented.
- (27) The display boards shall be functional and the cause list be displayed for convenience and information to all stakeholders.
- (28) Orders/Judgments passed by the Court and next date of cases shall be uploaded on the website of the concerning District at the earliest.
- (29) In order to avoid physical contact, the drop box system to receive applications / petitions etc. in the Court for which filing counter is not provided, be adopted by respective Courts, in such matters the party concern / his advocate shall mention his e-mail ID and mobile number on applications / petitions etc.
- (30) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.

- (31) As Government advisory has required restricted movements for persons aged 65 years and above, learned Advocates / Senior Advocates aged 65 years and above are requested to exercise due caution / avoid physical appearance in the Courts.
- (32) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and Deputy Administrative Officer, wherever available / one senior court staff, shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions. The Committee shall report the District Judge.
- (33) No function or any other event shall be permitted inside the Court premises.
- (34) District & Sessions Judges are authorized to make any suitable changes according to the prevailing situation of any court in his jurisdiction for smooth functioning of courts and also for management for preventing the spread of Corona Virus in the matter of entry and sitting of the advocates, litigants etc. in court premises, under intimation to the High Court.
- (35) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.
- (36) If any advocate(s) or litigant(s) is found violating the above guidelines, the District Judge / Principal Judge shall bring it to the

notice of the Bar Council of Madhya Pradesh and respective Bar Association(s) under intimation to the High Court and may take such action as he/she deems fit and proper.

- (37) From the date of implementation of this Circular, the Units criteria shall be relaxed to 50% of the prescribed Units till further order / modification.
- (38) The Units criteria relaxed as per Circular no. A/2874, dated 03.12.2020 shall remain extended upto implementation of this Circular.


15.1.21
(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL